

युद्ध के बढ़ते हुए खतरे और शांति के लिए संघर्ष

जनरल कार्डिनल की यह बैठक, तनाव-रहित को कमजोर करने तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने के अमरीका के सोचे-समझे हुए अभियान पर गंभीरतापूर्वक गौर करती है। इस अभियान ने विश्व शांति को संकट में डाल दिया है और फौजी टकराव का खतरा पैदा कर दिया है जिसमें आणविक अस्त्रों तथा न्यूट्रान बमों का इस्तेमाल भी संभव है। हथियारों का भारी जलीरा खड़ा करने और अपने विभिन्न फौजी ग्रहों का आधुनिकीकरण करने की अमरीकी कार्रवाई साफ तौर पर यही साबित करती है कि अमरीका तेजी से युद्ध की तैयारियाँ कर रहा है। 1982 के लिए रीगन प्रशासन द्वारा 136 अरब डालर का सुरक्षा बिल पेश किया गया है जो अमरीका के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा फौजी कदम है और इससे पिछले साल की तुलना में 26.4 अरब डालर ऊँचा है। यह बैठक न्यूट्रान बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के रीगन प्रशासन के फैसले की कड़ी निंदा करती है। संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए नरसंहार करने का यह वैश्विक हथियार मनुष्यता के विरुद्ध अपराध है।

अफगानिस्तान की जनता के प्रति सोवियत समर्थन तथा किसी भी बातचीत के लिए सोवियत फौजों की विला शर्त वापसी को शर्त बनाकर रीगन प्रशासन निरस्त्रीकरण से संबंधित बातचीत को अनिश्चित काल के लिए टालता आ रहा है। ईरान से लड़े जाने के बाद अमरीका अब दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया में अपने ग्रहों को तेजी से बढ़ा रहा है। दियौंग गासिया में वायु तथा समुद्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 30 करोड़ डॉलर का एक ठेका दिया गया है। इस प्रभु का काम पूरा हो जाने पर यहाँ 2,150 सैनिकों का अमाव होगा। इस ग्रह से भीमकाय सी-5 मालवाहक विमानों को उड़ाया जा सकेगा और उधर, समुद्री क्षेत्र में, विमानवाहक पोतों को लारण तथा जा सकेगी। अमरीका ने अब ओमान, सोमालिया तथा केनिया में भी ग्रहा बनाने की सुविधाएँ हासिल कर ली हैं और वह इन देशों में अमरीकी ताकत को बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ डॉलर खर्च करने जा रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवादी दक्षिण एशिया में यहूदीवादी इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारबंद कर रहे हैं और उसे ताकतवर व हमलावर ताकत के रूप में विकसित किया जा रहा है। अरब देशों की फूट तथा अमरीकी बढ़ावे से यहूदीवादी शासक इतने डरे हो गये हैं कि उन्होंने इराक के नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया और लेबनान पर अपने हमलों तथा लूट को बराबर जारी रखे हुए हैं। यहूदीवादियों की और अधिक फौजी मदद देने के अमरीकी फैसले ने पश्चिम एशिया के देशों के लिए भी साफ-साफ खतरा पैदा किया ही है, यूरोप के देशों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। यूरोपीय देशों ने इस कदम के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है।

इस बैठक का दृढ़ विश्वास है कि अमरीकी शासकों के ये

कदम यही बताते हैं कि यूरोप और एशिया के चारों ओर एक रणनीतिक घेरा खींचने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे एकमात्र नीयत यही है कि इस क्षेत्र में समाजवाद के प्रभाव को रोका जाय।

यह बैठक शांति की रक्षा के लिए जारी संघर्ष में आ रही गति पर ध्यान देती है और शांति की ताकतों—सोवियत के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के देश जिसकी पहली कतारों में हैं—को पूरा-पूरा समर्थन देती है।

यह बैठक, अमरीकी साम्राज्यवादियों की ओर से युद्ध के बढ़ते हुए खतरे तथा विश्व शांति के लिए पैदा हुए संकट को पहचानने के लिए मजबूर वर्ग को आगाह करती है और मजबूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह हमारे देश की तमाम जनता को एक और विश्व-युद्ध थोपने की इस घिनौनी साजिश के खिलाफ लामबंद करे। सुनिया-भर के मजबूर आंदोलन से नजदीकी सहयोग करते हुए युद्धोन्मादियों की साजिश को शिकस्त देना और विश्व शांति की रक्षा करना तभी संभव होगा।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारबंद किये जाने पर

जनरल कार्डिनल की यह बैठक, अमरीका द्वारा पाकिस्तान के फौजी शासकों को एफ-16 विमानों तथा दूसरे विकसित प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइलों) से बड़े पैमाने पर हथियारबंद किये जाने पर गहरी चिंता के साथ गौर करती है। इसकी खबरें भी मिली हैं कि पाकिस्तान के फौजी शासकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमरीका से नवीनतम विध्वंसक विमान हासिल करने का सोदा भी पूरा कर लिया है। एफ-16 विमानों की तरह इस विमान में भी मिसाइलें लगी हुई हैं जो भारत के किसी भी हिस्से में मार कर सकती हैं। भारत की जनता को पाकिस्तान के शासकों द्वारा शुरू किये गये तीन-तीन युद्धों का सामना करना पड़ा है। स्वाभाविक रूप से इससे वह बहुत चिंतित है।

यह बैठक मजबूर वर्ग को आगाह करती है कि दियौंग गासिया में पूरे साजो-सामान से युक्त फौजी ग्रहा कायम करने के बाद अब अमरीकी साम्राज्यवादी दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में और भी नये-नये ग्रहों कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र में उनकी इस रणनीति के केंद्र में है। पाकिस्तान पर "सोवियत खतरे" का मुकाबला करने के बहाने से अमरीकी साम्राज्यवादी, इस उपमहादीप में पांव जमाने के लिए पाक फौजी तानाशाह को हथियारबंद कर रहे हैं। अमरीका जहाँ पाकिस्तान को अपनी नाभिकीय क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वहाँ भारत के मामले में तारापूर संयंत्र को यूरोनियम देने संबंधी पिछले समझौते को पूरा करने से इनकार कर रहा है। साफ तौर पर, इसके पीछे संशय यही है कि भारत सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जाय कि वह

सोवियत संघ के खिलाफ अमरीकी साइन पर चले और उसकी हार् में ही मिलाये। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चीन का जनवादी गणतंत्र पाकिस्तान के कोजी तानाशाह को अमरीका द्वारा हथियारबंद किये जाने को समर्थन दे रहा है।

पाकिस्तान शाक्यों को दो जी जा रही अमरीकी मदद, वहाँ की जनता के खिलाफ तानाशाही शासन की ताकत को बढ़ाती है। इसके साथ-साथ इसके पीछे, एशियाईयों को एशियाईयों से लड़ाने की अमरीकी साजिश भी काम कर रही है। यह बैठक,

सीटू की जनरल काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव

लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए बहादुराना संघर्ष चलाने पर, पाकिस्तान के मजदूर वर्ग और वहाँ की जनता को तहेदिल से दोस्ताना मुबारकबाद देती है। पाकिस्तान और भारत दोनों की जनता को, दोनों देशों के बीच तनाव तथा युद्ध का, विरोध करना होगा।

यह बैठक आग्रह करती है कि साम्राज्यवादी सहायता पर अपनी निर्भरता तथा तानाशाहीपूर्ण-जनविरोधी नीतियों के अंतर्गत शासक पार्टी, अमरीकी साजिशों का मुकाबला करने और देश की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए देश की जनता को सामबंद नहीं कर सकती। इसलिए, दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए, जनतंत्र में विश्वास रखनेवाली जनता को, हरकत में लाने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी मजदूर वर्ग और सर्व-हारा ताकतों की ही है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी पूर्णता करने का मतलब मजदूर वर्ग के लिए खुद अपने भविष्य को खतरे में डालना होगा। □

छठी पंचवर्षीय योजना पर

1981 के 21 से 24 अगस्त तक हावड़ा में हुई सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक, योजनाओं की पूर्ण फिल्लता की ओर मजदूर वर्ग और देश की जनता का ध्यान खींचना चाहती है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह सचाई खुलकर सामने आ गयी है। इस योजना में बड़े ही शर्मनाक तरीके से आम जनता पर धोखा करने, उस पर और ज्यादा बोझ लावने की वकालत की गयी है जबकि, साधन-संपन्न वर्गों को रियायतें दी गयी हैं। योजना का दस्तावेज खुद अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और संकट की गहराई को बड़े साफ तौर पर दिखाता है।

योजना के दस्तावेज में स्वीकार किया गया है कि हजारों करोड़ रुपये पूँजी के बावजूद, योजना के खत्म होने के बाद, कम से कम साढ़े 21 करोड़ लोग यानी कुल आबादी का 30% हिस्सा, गरीबी की रेखा के नीचे गुजर कर रहा होगा। यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि आबादी का 48% हिस्सा आज गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहा है। और, इस हालत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इसे देखते हुए योजना का यह दावा वास्तविक स्थिति को बहुत ही हल्का करके दिखाने की कोशिश है।

मिसाल के तौर पर, योजना के दस्तावेज में स्वीकार किया

गया है कि योजना के शुरू होने के समय तक 2 करोड़ 21 लाख लोगों को रोजगार दिये जाने का काम बाकी था। दस्तावेज में यह भी स्वीकार किया गया है कि योजना के पांच सालों के दौरान 3 करोड़ 20 लाख नये लोग रोजगार के बाजार में होंगे। योजना बनानेवाले 3 करोड़ लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने का शेखी भरा दवा कर रहे हैं। सचाई यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के बढ़ने की दर महज 8 लाख सालाना रही है, इसीलिए खुद-रोजगार का जगूफा छोड़ा गया है जो रोजगार की उम्मीद लगाये बैठे लोगों के साथ धोखाधड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। रोजगार दफ्तरों के चालू रिकार्ड के अनुसार दिसंबर 1980 तक ऐसे लोगों की संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी थी। पिछली तमाम योजनाओं के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही रही है और यह योजना भी इस दिशा को बदल नहीं सकेगी।

योजना बनानेवालों का अनुमान है कि शहरी आबादी का करीब पांचवां हिस्सा कच्ची बास्तियों में रह रहा है। उनके अपने अनुसार 1985 तक ऐसे लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोगों के

सीटू सरकुलर नं० 22/81

प्रिय साथियों,

बेलूर-हावड़ा में 21-24 अगस्त, 1981 को संपन्न जनरल काउंसिल की बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाये हैं। इसने यह नोट किया है कि अमरीकी साम्राज्यवादी ज्यादा से ज्यादा सनमाने कदम उठा रहे हैं जिससे एक और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। बैठक ने संपत्ति को बनाए रखते हुए नरसंहार करने के अमानवीय हथियार—प्यूट्रान बम को भारी मात्रा में बनाने के रीगन प्रशासन के फैसले की निंदा की है। पाकिस्तान को नवीनतम हथियारों से लैस करने के अमरीकी फैसले ने युद्ध के खतरे को हमारी दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व की विपक्षी हुनरी स्थिति की पूष्टभूमि में ये कदम हमारे देश की स्वतंत्रता को घमकी हैं। युद्ध के बढ़ते हुए खतरे व शांति के लिए संघर्ष तथा "अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारबंद करने" पर प्रस्तावों में इस विषय पर हमारे विचार दिये गए हैं। यह नोट किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बारे में जनता को सचेत करने तथा अभियान चलाने में और शांति व अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग को तैयार करने में सीटू यूनियनों पीछे हैं।

राष्ट्रीय स्थिति पर, बैठक ने छठी पंचवर्षीय योजना पर एक प्रस्ताव अपनाया जो यह नक़्शा पेश करता है

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

लिए आवास की सुविधा की जरूरत होगी. योजना बनानेवालों का इनमें से सिर्फ 21 लाख लोगों के लिए आवाससुविधा जुटाने का इरादा है. बाकी साढ़े तीन करोड़ लोगों को, अतुल्य जैसे लोगों और उनके भाई-बिरादरों की मेहरबानी पर, कच्ची बस्तियाँ या फुटपाथों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जायगा. ग्रामीण क्षेत्र में आवास की स्थिति के सिलसिले में योजना बनाने वालों का अनुमान है कि एक करोड़ 45 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए मदद की जरूरत होगी. इनमें से 77 लाख को घर बनाने के लिए जमीन दी जा चुकी है, लेकिन, जहाँ तक घर बनाने के लिए सहायता का सवाल है, वह सिर्फ 5 लाख 60 हजार परिवारों को ही दी गयी है.

योजना बनानेवालों ने किसानों के पक्ष में भूमि सुधारों को सक्ती से लागू किये जाने का सुझाव देने के बजाय 5 एकड़ से ऊपर की ज़ोनों की अतिरिक्त भूमि के सिर्फ 15% हिस्से को अधिग्रहण का सुझाव देकर, एक तरफ बड़े जमींदारों को नयी रियायतें दी हैं और दूसरी ओर मंजोल किसानों पर हमला किया है. लगातार बढ़ती हुई कीमतों तथा ख़ाली लगाकर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण खेतमजदूरों तथा किसानों की क़यशक़ित लगातार घटती जा रही है. इसके बावजूद योजना बनानेवालों ने खेतमजदूरों को पूरा-पूरा रोजगार तथा उचित मजूरी दिलाने के लिए उचित कदम उठाने और किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी कीमतें दिये जाने का प्रस्ताव नहीं किया है.

समाज के इन गरीब तबकों को मदद पहुंचाने के नाम पर यह योजना तैयार की गयी है. इस योजना के एक हिस्से को तो दो अंकों में बँट रही मुद्रास्फीति पहले ही चट कर चुका है. योजना को पूरा करने के लिए साधन जुटाने की जो योजना पेश की गयी है उससे पता चलता है कि इसका असली बोझ जनता पर ही पड़नेवाला है, जबकि पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन के नाम पर साधन-संपन्न वर्गों को इस बोझ से बरी रखा गया है. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को यह सलाह तो दी गयी है कि कीमतें बढ़ाकर अपने पाठों को कम करें, लेकिन इन पाठों की असली बजहों, अर्थात्चार कुव्यवस्था तथा क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न किये जाने आदि के खिलाफ कदम उठाये जाने की कोई सलाह नहीं दी गयी है. योजना बनानेवाले अपनी संपत्ति को पहले के मुकाबले कहीं तेज रफ़्तार से फँला रहे, विदेशी तथा भारतीय इज़ारेदार घरानों के राष्ट्रीयकरण की मांग भी नहीं करते. लेकिन, योजना बनानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों के उत्पादनों की कीमतें बढ़ाने, लाघान, लायों आदि पर दी जाने-वाली राहत (सब्सिडी) को खत्म करने और अग्रत्यक्ष कर थोपने आदि के जरिये लगभग 21,302 करोड़ के साधन जुटाने के लिए आम जनता पर हमला करना नहीं भूलते. इसके अलावा, योजना में 5,000 करोड़ के करीब के घाटे की, जो योजना के अंत तक इससे कम से कम दुगना तो जरूर ही बैठेगा, व्यवस्था रखी गयी है. इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी तथा कीमतें और भी ऊपर चढ़ जायेंगी.

योजना बनाने वाले विदेशी सहायता पर निर्भर हैं. उनके अनुमान के अनुसार 10,000 करोड़ की नक़द या कुल 20,000 करोड़ की विदेशी सहायता की जरूरत होगी. इस सहायता को

हासिल करने के लिए जैसा कि विदेशी गठबंधनों की संख्या से साफ है, विदेशी इज़ारेदार कंपनियों को तरह-तरह की रियायतें दी गयी हैं. 1979 की तुलना में, स्वीकार किये गये विदेशी गठबंधनों की संख्या दुगनी होकर 596 के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गयी है. तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों समेत, अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में विदेशी पूंजी की घुसपैठ हो चुकी है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जा रही इन रियायतों ने हमारे देश को करीब-करीब गिरवी ही रख दिया है. इसके ऊपर से भुगतान संतुलन का बढ़ता ह्रास घाटा है जिसके चलते सरकार को 4,500 करोड़ के कर्ज़ के लिए ब्राइ एम एफ से सौदेबाजी करनी पड़ रही है. इस सारी स्थिति ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था और उसके साथ ही ट्रेड यूनियन आंदोलन दोनों के लिए ही भारी क्षतरा पैदा कर दिया है. देश में हुए हड़ताल संपर्कों के बरबर दमन तथा अनिवार्य सेवा आयादेश के जरिये हड़तालों पर पाबंदी लगाये जाने जैसे कदम इसीलिए उठाये गये हैं ताकि ब्राइ एम एफ मेहरबान हो सके.

संगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा कर्मचारियों को हमलों का निशाना बनाने के लिए चुना गया है. योजना में पेश की गयी वेतन तथा श्रम नीति, उन पर वेतन ज़ाम थोपने तथा मजूरी में कटौती करने की ही नीति है. बोस को उत्पादन से जोड़ने की योजना का प्रस्ताव करके योजना बनानेवालों ने, बोस के स्थान पर मजूरी होने की धारणा पर हमला किया है. इसके अलावा उन्होंने यह भी सलाह दी है कि आधा मजूरी में कोई बड़ोती उत्पादन के आधार पर हो. मजूर किसी एक कारखाने या उद्योग में यदि उत्पादन बढ़ा भी लेते हैं तब भी उन्हें अपनी मेहनत का उचित मुआवज़ा नहीं मिलनेवाला है. इसके लिए उन्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि सारी की सारी अर्थ-व्यवस्था नहीं सुधर जाती. श्रम की असमानताओं के नाम पर योजना बनानेवालों ने, मजदूर और मजदूर की श्रम के बीच की असमानता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और इस असमानता को कम करने के नाम पर वेतनों में कटौती का प्रस्ताव किया है. लेकिन ये सारा स्वांग करने के बावजूद शोषक तथा शोषित वर्गों के बीच की भारी असमानताओं को कम करने और बड़े सरमायेदारों, इज़ारेदारों, तथा जमींदारों की श्रामदनी पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.

इसलिए, यह बैठक पूंजीवादी योजना की वीवालिया नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज़ करती है और मांग करती है कि, विदेशी ऋणों के भुगतान को फौरन स्थगित किया जाय, भारतीय तथा विदेशी दोनों ही तरह के इज़ारेदार घरानों के राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीपतियों के ऊँचे मुनाफों पर प्रत्यक्ष कर लगाकर साधन जुटाये जाय, शोषक वर्गों तथा मेहनतकश जनता के बीच की श्रम की असमानता को कम करनेवाली सही तरह की वेतन तथा श्रम नीति लागू की जाय, अनिश्चित भूमि का गरीब किसानों के बीच वितरण किया जाय, किसानों को अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया जाय, खेतमजदूरों को उचित मजूरी दिलायी जाय, बेरोजगारों को बेकारी सहायता दी जाय और कमज़ोर तबकों की स्थिति को सुधारने के लिए दूसरे कदम उठाये जाय.

□